iRAD (एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस) प्रशिक्षण कार्यक्रम - मध्य प्रदेश

गृह विभाग मध्य प्रदेश द्वारा iRAD परियोजना के संबंध में सभी हितधारकों के ज्ञानवर्धन व जागरूगता लाने के उद्देश्य से राज्य और जिला दोनों स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बृहत श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मध्य प्रदेश के राज्य व जिला केंद्रों एवं NICSI के सहयोग से सभी संबंधित विभागों के लिए राज्य और जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं।

वर्ष 2024 में अप्रैल-मई माह के दौरान राज्य के सभी 52 जिलों में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम लगभग 500 ओरिएंटेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए और लगभग 3000 अधिकारियों-कर्मचारियों को परियोजना के उद्देश्यों व प्रक्रियाओं संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान कर प्रशिक्षित किया गया।

iRAD (एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस) अब eDAR (विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट) के नाम से प्रचलित परियोजना सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, और इसे दुर्घटना प्रबंधन एजेंसियों के जमीनी स्तर के कर्मचारियों के समन्वय के साथ आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वैज्ञानिक तरीके से सड़क दुर्घटना के खतरे को कम करने के लिए विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावी दुर्घटना प्रबंधन, विश्लेषण और नीति निर्माण की सुविधा के लिए सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी का एक केंद्रीकृत और व्यापक डेटाबेस बनाना एवं प्रबंधन मे उपयोग करना है।

इस परियोजना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मध्य प्रदेश द्वारा मार्च 2021 से राज्य के सभी 52 जिलों में सभी चार हितधारक विभागों (पुलिस, परिवहन, सड़क स्वामित्व एजेंसियां और स्वास्थ्य) के सहयोग से लागू किया गया है। मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग ने इसमे अब तक 1,62,000 से अधिक दुर्घटनाएं दर्ज की हैं और वह iRAD के कार्यान्वयन के संबंध में अग्रणी श्रेणी मे है |

ऐसे सतत प्रयासों के साथ iRAD परियोजना मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा सुधारों पर स्थायी प्रभाव डालने के लिए निरंतर प्रयासरत है, तथा परियोजना के मुख्य घटक के रूप मे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मध्य प्रदेश iRAD के मूल उद्देश्य भारत में सड़क सुरक्षा यानी 'सभी के लिए सुरक्षित सड़क' के पूर्णता मे सहयोग हेतु करने के लिए सदा तत्पर है।

प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुछ झलकियाँ

जिला अलिराजपुर

जिला अनुपपुर

जिला मंदसौर

जिला सीधी

iRAD (Integrated Road Accident Database) Training Program - Madhya Pradesh

For furthering effective implementation of iRAD Project, Department of Home, Madhya Pradesh mandated to organize a series of training programs at both the state and district levels with the aim of enhancing the knowledge and awareness of all the stakeholders. For this, large scale training campaigns are being run at the state and district level for all the concerned departments with the help of National Informatics Centre, State and District Centers of Madhya Pradesh and NICSI.

During the month of April-May in the year 2024, about 500 orientation programs were successfully organized through online or offline medium in all 52 districts of the state and about 3000 officers-employees were trained by providing necessary information regarding the objectives and procedures of the project.

The iRAD (Integrated Road Accident Database) project now known as eDAR (Detailed Accident Report) is an important initiative of the Ministry of Road, Transport and Highways (MoRTH), Government of India, and is being implemented with the coordination of ground level staff of accident management agencies. Developed to reduce the risk of road accidents in a scientific manner using modern information and communication technology.

The project has been implemented by National Informatics Centre, Madhya Pradesh from March 2021 in collaboration with all the four stakeholder departments (Police, Transport, Road Owning Agencies and Health) in all 52 districts of the state. Madhya Pradesh Police Department has recorded more than 1,62,000 accidents so far and is in the leading category in terms of Implementation and usage of iRAD.

With such ongoing efforts, the iRAD project continues to make a lasting impact on road safety improvements in Madhya Pradesh. National Informatics Centre, Madhya Pradesh also is committed to support the core objective of iRAD i.e. improve road safety in India .

News Clippings

आईआरएडी पोर्टल पर पुलिस को दिया गया दो दिवसीय प्रशिक्षण

सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी की जाएगी एकत्रित और विश्लेषित

भास्कर ब्यूरो, सीधी

आईआरएडी पोर्टल के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए पुलिस अधिकारी और कर्मचारी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना आईआरएडी को पूरे देश में लागू किया है। यह परियोजना आईटी आधारित प्रणाली पर प्रस्तावित है, जिसमें कॉन्फिगर किए गए मोबाइल ऐप और टैबलेट का उपयोग करके दुर्घटना स्पॉट से डेटा कैप्चर किया जाएगा। इस परियोजना के तहत विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य है। इस डेटा का विश्लेषण करके सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों की पहचान की जा सकेगी, जिससे उन्हें रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाए जा सकेंगे, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सके। पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य संबंधित विभागों के उपयोग के लिए दुर्घटनाओं के डेटा को व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इस परियोजना के अंतर्गत देश भर में सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी एकत्रित और विश्लेषित की जाएगी, जिससे नीतियों और योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। यह पहल न केवल सड़क सुरक्षा में वृद्धि करेगी, बल्कि दुर्घटनाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान को भी कम करने में सहायक होगी। पुलिस अधीक्षक डॉ रवींद्र वर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं यातायात थाना प्रभारी की अध्यक्षता में एनआईसी कलेक्ट्रेट में आईआरएडी के नवीन मॉड्यूल को लागू करने के उद्देश्य से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला सत्र सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण सत्र के पहले दिन पुलिस उपखंड चुरहट के अंतर्गत थाना रामपुर नैकिन, चुरहट, कमजी तथा अमिलिया के थाना प्रभारी, चौकी पिपरांव, सेमरिया, एवं सिहावल के प्रभारी स्थित कुल 30 पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। दूसरे दिन पुलिस उपखंड सीधी और कुसमी अंतर्गत थाना कोतवाली सीधी, जमोड़ी, बहरी, मझौली, कुसमी एवं भुईमाड़ थानों के प्रभारी, उपनिरीक्षक, सहित आईआरएडी पोर्टल का उपयोग कर रहे विवेचना अधिकारी एवं सीसीटीएनएस ऑपरेटर आदि कुल 45 पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। आईआरएडी एप एवं पोर्टल पर कार्य करने का प्रशिक्षण एनआईसी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी दशरथ प्रजापति के मार्गदर्शन में आईआरएडी प्रभारी जिला रोलआउट प्रबंधक आशुतोष सिंह ने दिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आईआरएडी पोर्टल के उपयोग में दक्ष बनाना था, जिससे वे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर विवेचना कार्य को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बना सकें। समारोह में सभी उपस्थित अधिकारियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी बताया और इसे अपने दैनिक कार्यों में लागू करने का संकल्प लिया।

मंडला पुलिस की एक दिवसीय कार्यशाला

मंडला, देशबन्धु। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार आज दिनांक 27/05/24 को थाना यातायात में पुलिस अधीक्षक मंडला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडला के निर्देशन में पोर्टल पर जिले मे सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरणों की ऑनलाइन डाटा एंट्री की जा रही है थाना स्तर पर इसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण में उपयोग एवं बैकलॉग डाटा एंट्री के बारे में जिले के पुलिस अधिकारी/ कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी एवं अधिकारी/ कर्मचारियों को आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उचित समाधान प्रदाय करने हेतु जिले के डिस्ट्रिक्ट रोल आउट मैनेजर अभिजीत सोनवानी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया ।

सड़क दुर्घटनाएं रोकने कार्यशाला में बनी योजना

नवभारत सीहोर. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से बचाव एवं सुरक्षित यातायात के लिए एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना प्रारंभ की गई है, जिसमे देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है.

इसके लिए भारत सरकार द्वारा एकीकृत पोर्टल तथा मोबाइल एप्प बनाया गया है, जिसे सड़क दुर्घटना की विवेचना सम्बन्धी समस्त विभाग जैसे पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला परिवहन विभाग, नगरीय निकाय विभाग और राष्ट्रिय राजमार्ग विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं अन्य सड़क निर्माण एजेंसी, बीमा कंपनियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है. इस व्यवस्था को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार द्वारा विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित किया गया. इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक मर्यक अवस्थी ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं थाना प्रभारियों से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की एवं जिले में विगत वर्ष 2021 के पश्चात हुई समस्त दुर्घटनाओं की जानकारी एक सप्ताह में पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिया, साथ ही दुर्घटनाएं रोकने पर भी चर्चा हुई.

संकलन (मनोज कुमार शर्मा),निदेशक (आईटी)
एनआईसी मध्य प्रदेश राज्य केंद्र।